फरीदाबाद
मजदूर समाचार
हर जगह, सब से, जब भी समय मिले

'मजदूर समाचार' की कुछ सामग्री अंग्रेजी में इन्टरनेट पर है। देखें–
< http://faridabad majdoorsamachar.blogspot.in >

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन.आई.टी. फरीदाबाद - 121001

नई सीरीज नम्बर 322 1/– अप्रैल 2015

कुछ अस्थाई मजदूरों की बातें

मजदूर समाचार के दिसम्बर 2014 अंक में प्लॉट 399 सैक्टर-8, आई.एम.टी. मानेसर स्थित अस्ती इलेक्ट्रोनिक्स फैक्ट्री में मजदूर हलचलों का विवरण कुछ विस्तार में है। अस्ती मजदूरों की बातें जून 2014 और जनवरी 2015 अंकों में भी हैं। इधर अस्ती इलेक्ट्रोनिक्स के कुछ अस्थाई मजदूरों से 4-4½ घण्टे बातचीत हुई। हमें लगता है कि इन युवा मजदूरों के अनुभव तथा विचार सब के लिये उल्लेखनीय महत्व के हैं। यहाँ प्रस्तुत हैं।

✶ 125 स्थाई और ठेकेदारों के जरिये रखे 350 मजदूरों में तालमेल बढे। अपने को और मजबूत करने के लिये दो अस्थाई तथा एक स्थाई मजदूर नवम्बर 2013 में एक यूनियन लीडर से मिले। नेता बोला कि कुछ खर्चा होता है, चन्दा एकत्र करो, 7 स्थाई को फलाँ-फलाँ पद के लिये तैयार करो। "अस्थाई क्यों नहीं?" पूछने पर यूनियनवाला बोला कि कानून से ऐसा नही हो सकता। माथा ठनका तो लीडर बोला कि ठेकेदारों के जरिये रखे सब को स्थाई करवायेंगे।

आपस में चर्चायें की। यूनियन पदों के लिये 7 स्थाई को तैयार किया। लीडर से 2 फरवरी 2014 को मिले। अस्थाई मजदूरों ने 4 लाख 66 हजार रुपये और स्थाई ने दो लाख से ज्यादा एकत्र किये।

कम्पनी को पता चल गया। पद वाले 2 को 10 फरवरी को बाहर कर दिया। मजदूरों द्वारा मिल कर कदम उठाने की बात पर वे दो बोले कि कानून करेगा, बड़ा लीडर केस देख रहा है, जल्दी ही अन्दर आ जायेंगे। फिर 17 फरवरी को वही बोले कि सब कर लिया, कुछ नहीं हुआ, आप लोग कुछ करो।

18 फरवरी को सुबह 8 बजे सब अस्थाई और अधिकतर स्थाई मजदूर कार्यस्थल छोड़ कर फैक्ट्री में खुले स्थान पर एकत्र हो गये। काम बन्द होते ही मैनेजमेन्ट में हड़कम्प। श्रम विभाग से इन्सपैक्टर पहुँचा। बैठे दिनों के पैसों के साथ उन दो को वापस लेने का समझौता दोपहर ढाई बजे हुआ।

फरवरी की तनखा मिली तब स्थाई और अस्थाई ने एक-एक लाख से ज्यादा एकत्र किये। मार्च 2014 में यूनियन के पास 9 लाख रुपये।

कम्पनी ने गियर बदला। यूनियन बॉडी से बात की। रजिस्ट्रेशन के लिये प्लान्ट हैड की गाड़ी में यूनियन बॉडी के दो लोग चण्डीगढ जाने लगे। यूनियन रजिस्ट्रेशन 17 मई 2014 को आ गया।

मई में ही कम्पनी ने स्थाई मजदूरों को शिक्षा देने के लिये तीन बन्दे बुलाये। प्रत्येक को 15 दिन के डेढ लाख रुपये दिये। पढाया : अपना जीवन बेहतर कैसे किया जा सकता है ; आगे बढने के लिये कौन से तरीके अपनाये जाते हैं ; मैनेजमेन्ट और मजदूरों के बीच रिश्ते कैसे होने चाहियें। और अन्त में वे कहते — अपनी तरक्की के लिये साम, दाम, दण्ड, भेद सब अपनाने चाहियें यह चाणक्य कहता था।

अस्थाई मजदूरों ने एतराज किया। यह फूट डालने के लिये है। ब्रेन वाश कर रहे हैं। कम्पनी की रणनीति को समझो। इस पर लीडर कहते कि यह कम्पनी की नीति है, यूनियन इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। तो अस्थाई को भी यह शिक्षा दिलवाओ के उत्तर में लीडर कहते कि यह ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों के लिये नहीं है।

✶ यूनियन ने मैनेजमेन्ट को माँग-पत्र दिया। उत्तर : कम्पनी घाटे में है, मुनाफे में आयेगी तब बात करेंगे। दबाव डालने के लिये यूनियन ने मजदूरों से काम धीमा करने को कहा। कम्पनी ने रात को 12 घण्टे की नई शिफ्ट के लिये नये ठेकेदार के जरिये 150 नये वरकर रखे। इस से स्लो डाउन का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा, मजदूरों ने यूनियन से इसे रोकने को कहा तो लीडर बोले कि बाहर से मजदूर लाना कम्पनी का अधिकार है।

काफी उत्पादन कम्पनी बाहर करवाने लगी। जापान, चीन, वियतनाम से और आई.एम.टी. में अनु ऑटो, भगवती ऑटो, मदरसन्स, श्रीनिसन्स, दूत वायर से उत्पादन प्राप्त कर गोदामों में 4 महीने का माल जमा किया। मजदूरों ने एतराज किया तो यूनियन लीडर बोले कि कुछ नहीं कर सकते, कम्पनी का अधिकार है, कहीं से माल बनवा सकती है। जुलाई 2014 में मैनेजमेन्ट-यूनियन तीन वर्षीय समझौता हो गया।

✶ अक्टूबर-आरम्भ में बात फैली कि ठेकेदारों के जरिये रखे सब मजदूर नौकरी से निकाले जायेंगे। अस्थाई मजदूर यूनियन बॉडी से मिले और जानकारी माँगी। लीडर बोले कि झूठी अफवाह है, एक भी अस्थाई के बाहर किये जाने से पहले यूनियन बॉडी के वे 7 बाहर जायेंगे।

31 अक्टूबर को रात चर्चा : किसी भी क्षण सब अस्थाई बाहर कर दिये जायेंगे। यूनियन प्रधान को अस्थाई मजदूरों ने 1 नवम्बर को सुबह पकड़ा तो वह बोला कि झूठ है, यूनियन आपके साथ है। वैसे, सब स्थाई को पता चल गया था कि सब अस्थाई निकाले जायेंगे, सतर्क रहना, इनके लफड़े में मत पड़ना, शिफ्ट छूटने पर गाड़ी में बैठ कर घर चले जाना।

1 नवम्बर को अस्थाई मजदूरों ने यूनियन बॉडी से, मुखर स्थाई मजदूरों से मीटिंग की। सब ने गोली दी, ऐसा कुछ नहीं है, टैन्शन मत लो।

ए-शिफ्ट दोपहर 3.30 पर समाप्त होती है। कम्पनी ने 3 बज कर 28 मिनट पर नोटिस लगाया। पढ कर सब अस्थाई मजदूर शान्त हुये, खुश हुये। फिर एक मिनट बाद कम्पनी ने दूसरा नोटिस लगाया: *"कम्पनी में काम की कमी होने के कारण ठेकेदारों के जरिये रखे सब वरकरों की एक हफ्ते की सवेतन छुट्टी की जा रही है और*

(शेष पृष्ठ तीन पर)

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद — 121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

कुछ सामान्य-रुटीन बातचीत

जे एन एस इन्सट्रुमेन्ट्स मजदूर : ''प्लॉट 4 सैक्टर-3, आई एम टी मानेसर स्थित फैक्ट्री में गलती पर स्कूल की तरह 10-20 मिनट एक जगह खड़ी हो जाओ की सजा लाइन लीडर देती हैं। खड़ा होने में कौन-सी शर्म है? काम से आराम ही मिलता है। पुरानी वरकर लाइन लीडर से, सुपरवाइजर से कैसे निपटें बताती हैं। इधर दो लाइन की लड़कियों ने मिल कर एक लाइन लीडर की फैक्ट्री में पिटाई की तब सुपरवाइजर ने आ कर उसे छुड़ाया।''

ओसवाल डाईकास्टिंग श्रमिक : ''प्लॉट 48-49 इन्डस्ट्रीयल एरिया, फरीदाबाद स्थित फैक्ट्री में 22 मार्च से लगातार ड्युटी है, साप्ताहिक अवकाश नहीं, 5 अप्रैल को शिफ्ट बदलेगी। लगातार 15 रात काम करना नाइट शिफ्ट वालों को बहुत भारी पड़ता है। मजदूरों में रोष होना स्वाभाविक है। कम्पनी कभी सप्ताह में दो छुट्टी कर देती है और कभी 15 दिन लगातार काम करो। मजदूरों को मशीन के पुर्जे बना रखा है। कम्पनी जब सप्ताह में दो छुट्टी करती तब हद तो यह है कि छुट्टी के पैसे मजदूरों को नहीं देती। ले-ऑफ, वे-ऑफ की बात यहाँ नहीं है — साप्ताहिक अवकाश के अलावा जिस दिन कम्पनी छुट्टी करती है उसका एक पैसा नहीं देती। यूँ भी, जब कम्पनी काम कम है कह कर छुट्टी करती है तब भी शिफ्टें 12-12 घण्टे की ही रहती हैं और ओवर टाइम का भुगतान दुगुनी दर से करने की बजाय सिंगल रेट से किया जाता है।''

लुमैक्स ऑटोमोटिव कामगार : '' प्लॉट 46 सैक्टर-3, आई एम टी मानेसर स्थित फैक्ट्री की स्थिति काफी समय से डाँवाडोल है। कम्पनी की दिल्ली में मायापुरी वाली फैक्ट्री, फरीदाबाद की दो फैक्ट्रियाँ, गुड़गाँव में उद्योग विहार वाली फैक्ट्री और पुणे वाली फैक्ट्री बन्द हो गई हैं। उद्योग विहार और फरीदाबाद से आये स्थाई मजदूरों को जोड़ कर अब यहाँ 110 परमानेन्ट मजदूर हैं। ठेकेदार के जरिये रखे 150 वरकर हैं। मोल्डिंग विभाग में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं और बाकी में सुबह 7 से साँय 7 की शिफ्ट है। यहाँ ***होण्डा*** स्कूटर और ***मारुति सुजुकी*** कारों के प्लास्टिक पार्ट्स बनते हैं। इधर फरवरी-अन्त में होण्डा स्कूटर का एक मॉडल बन्द होने और 25 मार्च को दूसरा मॉडल बन्द होने से लुमैक्स में दो लाइन बन्द हो गई हैं। इधर जनरल मैनेजर, फिल्टर हैड, परचेज अफसर आदि निकाल दिये हैं या छोड़ गये हैं। दबाव के कारण कम्पनी ने स्टॉफ का पी. एफ. जमा किया है पर मजदूरों का एक वर्ष से फण्ड जमा नहीं किया है।''

वी एन जी इन्टरप्राजेज वरकर : ''प्लॉट 4 सैक्टर-24, फरीदाबाद स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में 150 मजदूर काम करते हैं। कैजुअल वरकर 35-40 हैं, तीन ठेकेदारों के जरिये रखे 110 हैं, स्थाई मजदूर एक भी नहीं है। ***यामाहा, होण्डा, अपाचे*** के पुर्जे बनते हैं पर यहाँ से सीधे नहीं जाते। कैजुअल हैल्परों की तनखा 5000 रुपये, ई एस आई नहीं पी एफ नही। ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूर पीस रेट पर, ई एस आई नहीं, पी एफ नहीं। पावर प्रेसों पर उँगली कटती रहती है। सेक्युरिटी वाले प्रायवेट में ले जा कर पट्टी करवा देते हैं। बस। फिर कम्पनी निकाल देती है। साबह लोग कहते हैं कि पीस रेट पर हो इसलिये अपनी सेफ्टी आप करो, कम्पनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है।''

सुबरोस ऑटो

जून 2014 में दो-ढाई घण्टे की बातचीत के बावजूद सैक्टर-8, आई एम टी मानेसर स्थित सुबरोस फैक्ट्री का मार्च से जून 2014 का घटनाक्रम हमें समझ में नहीं आया था। इधर कुछ-कुछ समझ में आने लगा है।

300 स्थाई मजदूर, तीन ठेकेदारों के जरिये रखे 500 वरकर, 300-400 डिप्लोमा ट्रेनी, 300 इंजीनियर सुबरोस फैक्ट्री में कार्यरत थे। गुपचुप प्रत्येक स्थाई मजदूर से 4000 रुपये यूनियन चन्दा लिया, प्रधान बने बन्दे ने पत्नी की बीमारी का बहाना बना कर 15 दिन की छुट्टी ली, चण्डीगढ जा कर यूनियन का रजिस्ट्रेशन लाया। सुबरोस में 2013 के अन्त में यूनियन बनी, एटक की यूनियन बनी।

मार्च 2014 में यूनियन ने सब की तनखा बढवाई और फिर गुड़गाँव में मीटिंग हुई। कम्पनी की बसें मजदूरों को कमला नेहरु पार्क ले कर गई। दो घण्टे मीटिंग चली। लीडरों ने भाषण दिये, खूब तालियाँ बजी। पार्टी हुई, चाय-नाश्ता सुबरोस यूनियन प्रधान ने करवाया।

यूनियन ने प्रोडक्शन बढवाने की बजाय घटवाया था। एक लाइन पर जहाँ 1100 एयर कंडीशनर बनते थे वहाँ अप्रैल 2014 से 850 करवा दिये। मई आरम्भ में सब डिप्लोमा ट्रेनी और ठेकेदारों जरिये रखे पुराने आई टी आई से यूनियन सदस्यता के लिये 100-100 रुपये लिये। अचानक सोमवार, 14 मई 2014 को सुबह की शिफ्ट लाने कम्पनी की बसें नहीं पहुँची। अलियर व बासगाँव में रहते 250 वरकर 7 बजे फैक्ट्री में गये। धारूहेड़ा, गुड़गाँव आदि से आते मजदूर अपने से पहुँचे, 7 बजे नहीं पहुँचे। कम्पनी बसें नोएडा सुबरोस फैक्ट्री से मजदूरों को लाई। आई एम टी फैक्ट्री में काम करते सब मजदूर फैक्ट्री के बाहर — सुबह 7 बजे जो 250 अन्दर गये थे वे भी 10 बजे बाहर आ गये थे। यूनियन प्रधान फैक्ट्री के अन्दर गया, रात 9 बजे आया। सब मजदूर उसका इन्तजार कर रहे थे।

कम्पनी ने 14 मई को सुबह ही 27 पुराने आई टी आई और डिप्लोमा ट्रेनी के गेट बन्द का नोटिस लगाया था। यूनियन प्रधान बोला कि मैं इन्हें अन्दर करवा रहा हूँ और मैं खुद 45 दिन बाहर रहूँगा। कोरे कागज पर कोई दस्तखत मत करना। जो भी कुछ करना होगा वह 45 दिन बाद करेंगे।

15 मई 2014 को बसें समय पर पहुँची। प्रोडक्शन बढा दिया — एक लाइन पर 1200 ए सी बनाये। फिर 28 मई को ए-शिफ्ट छूटते समय 37 वरकरों के कार्ड ले लिये। रोज 30-40 के कार्ड लेने लगे। तीन-चार वर्ष से काम कर रहे 400 वरकरों को महीने-भर में निकाल दिया।

निकाले जाने पर वरकर यूनियन प्रधान के घर गये, नहीं मिला। उसका फोन स्विच ऑफ। वैसे 25 मई से ही यूनियन प्रधान के 60 लाख रुपये ले कर चले जाने की बातें होने लगी थी। यूनियन प्रधान के साथ जो 4 लीडर थे वे 15 मई के बाद दिखाई नहीं दिये। जब से निकालना शुरू किया तब से एटक का कोई लीडर सुबरोस फैक्ट्री के पास दिखाई नहीं दिया। यूनियन प्रधान अलियर गाँव का था। उसके परिवार वाले बोले कि वह गाँव में अपना सुब कुछ बेच कर बीबी-बच्चों के साथ कहीं चला गया है।

6-7 महीने में कम्पनी ने 300 परमानेन्ट वरकर भी निकाल दिये। यहाँ फैक्ट्री में 2007 में उत्पादन आरम्भ हुआ था और आज सुबरोस में कोई पुराना मजदूर नहीं है।

अब अधिकतर वरकर अन्डर ट्रेनिंग हैं। झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में जयपुर से परे के पोलिटैक्निक कॉलेजों से सीधे डिप्लोमा ट्रेनी लाते हैं। इंजीनियर भी ट्रेनी हैं। ठेकेदारों के जरिये रखे 400 हैल्परों को ई एस आई व पी एफ की राशि काट कर 6760 रुपये। ठेकेदारों के जरिये रखे आई टी आई को काट-पीट कर 8400 रुपये। चार-पाँच सौ डिप्लोमा ट्रेनी को ई एस आई व पी एफ काट कर 7200 रुपये। इंजीनियर ट्रेनी 65-70 और उनको 11-12,000 रुपये। इंजीनियरिंग किये और डिप्लोमा किये लाइनों पर अगल-बगल में काम करते हैं। स्टाफ बहुत है। काम का भारी दबाव और डाँटना-चिल्लाना। हैल्पर, आई टी आई तीन-चार महीने में छोड़ जाते हैं — 6 महीने होने पर कम्पनी वैसे भी निकाल देती है। तीन वर्ष के लिये ट्रेनी डिप्लोमा वाले और इंजीनियर तो रोज ही छोड़ते हैं, रोज भर्ती होते हैं।

निमंत्रण

अप्रैल में 26 तारीख वाले रविवार को मिलेंगे। सुबह 10 से देर साँय तक अपनी सुविधा अनुसार आप आ सकते हैं। फरीदाबाद में बाटा चौक से थर्मल पावर हाउस होते हुए रास्ता है। ऑटोपिन झुग्गियाँ पाँच-सात मिनट की पैदल दूरी पर हैं।

Ph. 0129-6567014
E-mail < majdoorsamachartalmel@gmail.com >
E-mail < baatein1@yahoo.co.uk >

कुछ अस्थाई मजदूरों की बातें......(पृष्ठ एक का शेष)

आठवें दिन अपने-अपने ठेकेदार के ऑफिस में जा कर हिसाब ले लें।''

धोखाधड़ी से उबले अस्थाई मजदूर यूनियन बॉडी को वहीं खत्म करने को बढे — न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी।अस्थाई में से ही कुछ ने लीडरों की रक्षा की और उन्हें कम्पनी से बात करने को कहा। वो गये और फिर लौट कर नहीं आये।

अब यह देखिये : *''आज दिनाक 1.11.2014 को सभी यूनियन प्रतिनिधियों व प्रबन्धक प्रतिनिधियों की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपसी सहमति बनी —*

1. कम्पनी में कार्य की कमी के कारण तथा ग्राहकों से आर्डर की कमी के कारण यह आवश्यक हो गया है कि ठेकेदारों के सभी कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया जाये। इसमें समस्त यूनियन प्रतिनिधियों को कोई आपत्ति नहीं है।

2......, 3.........., 4..........., 5............. (हस्ताक्षर)

✶ 1 नवम्बर को बी-शिफ्ट को मैनेजमेन्ट ने अन्दर आने ही नहीं दिया। स्थाई चुपचाप बाहर निकल गये पर ए-शिफ्ट के अस्थाई मजदूर बाहर नहीं निकले।मेन प्रोडक्शन लाइन पर 180 महिला और 70 पुरुष मजदूर बैठ गये। एक घण्टे बाद थानेदार और ठेकेदार आये। मशीनों के पास बैठना कानूनन अपराध है, कैन्टीन में जा कर बैठो। मजदूर नहीं हिले। तब लाठी लिये 25-30 पुलिसवाले आये।

सब वरकर कैन्टीन में जा कर बैठ गये। पाँच लोग मैनेजमेन्ट से बात करने गये। कोई सुनवाई नहीं। रात के 9 बज गये..... हमारे पास भविष्य की कोई योजना नहीं थी और पुलिस तो थी ही। हम ने फैक्ट्री छोड़ने का तय किया।कम्पनी राजी-राजी महिला मजदूरों को वाहनों से उनके निवास स्थानों पर छोड़ने को तैयार हुई।

रविवार, 2 नवम्बर को हम ने आपस में चर्चायें की। इनकलाबी वालों ने हमें उकसाया था — यूनियन भलाई के लिये बनती है, यूनियन का साथ दो। उन्हें बुलाया। वे डर रहे थे कि वरकर मारेंगे। भरोसा दिया।आ कर इनकलाबी वालों ने श्रम विभाग के लिये पत्र लिखवाया। पत्र देने गये तो श्रम निरीक्षक सीधा बोला कि कम्पनी बन्द हो रही है। काफी बहस के बाद पत्र लिया और बोला कि जाँच करेंगे।

कम्पनी की तैयारी देखने के लिये अस्थाई मजदूरों ने सोमवार को आराम किया।नीली वर्दी में 5-600 स्त्री व पुरुष पुलिस फैक्ट्री को घेरे खड़ी थी।

4 नवम्बर 2014 को सुबह 6 बजे सब अस्थाई मजदूर फैक्ट्री पहुँचे। पुलिस, बाउन्सर, ठेकेदार, कम्पनी अधिकारी हमें गेट पर जाने ही नहीं दे रहे थे। हम वहीं तम्बू लगाने लगे।अदालत का 150 मीटर दूर का आदेश दिखाया — फर्जी था, 21 अक्टूबर को लिया था। पुलिस ने धक्का किया। हम ने 150 मीटर दूर तम्बू लगाया। वकील ने स्टे हटवाने के लिये 25 हजार माँगे। अस्थाई मजदूरों ने स्थाई मजदूरों, फैक्ट्री यूनियन, एच एम एस से मेल मिलाप की काफी कोशिशें की, असफल रही। स्थाई मजदूर फैक्ट्री में काम करते रहे।

✶ अस्थाई मजदूर अपने दम पर खड़े हुये। इनकलाबी, क्रान्तिकारी, बिगुल..... यह सब आये, हाइजैक करने की कोशिशें की पर हम ने किसी की चलने नहीं दी। उन सब को सलाहकार के तौर पर लिया। सलाह लेते थे। पहले दिन ही नमस्ते कर दिया था कि मानना, नहीं मानना हमारे हाथ में था।

एटक लीडर : एच एम एस ऐसे ही करती है। आप हमारे साथ आओ।आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे।

अस्थाई मजदूर : आप आये, अच्छी बात है। पर आपने नपीनो ऑटो में जो किया वह हम ने अच्छी तरह से देखा है।आप जा सकते हैं। नमस्ते।

सीटू लीडर : मोदी विरोध में बहुत कुछ बोले। मोदी ऐसे-ऐसे कानून ला रहा है जो मजदूरों का भविष्य खराब कर देंगे।उन कानूनों को पास होने से रोकना है।

अस्थाई मजदूर : आप बड़े बुजुर्ग हैं।आपको बहुत नॉलेज है। पर यह राजनीतिक मंच नहीं है। यह मजदूर मंच है। वो कानून तो अभी आये भी नहीं हैं। हम तो पहले ही बर्बाद हो गये। वर्तमान में जो कानून हैं उन्हें तो लागू करवा नहीं पा रहे और भविष्य के लिये हाँक रहे हैं।

जब बिगुल वाले आये तब इनकलाबी वालों ने विरोध किया।क्यों आये ? उन्हें मंच से बोलने का समय नहीं दिया जाये।

अस्थाई मजदूर : यह इनकलाबी वालों का मंच नहीं है।यह ठेका मजदूरों का मंच है। किसको बोलना है, किसको नहीं, इसका निर्णय हम करेंगे।

✶ दबाव की आस में 2 पुरुष और 5 महिला मजदूरों ने 25 नवम्बर से 11 दिसम्बर तक भूख हड़ताल की। बिना किसी समझौते के अनशन समाप्त किया।

डी सी गुड़गाँव : भूख हड़ताल करने को मैंने कहा था क्या? ब्लैकमेल कर रहे हो। बाहर जाओ। श्रम विभाग का मामला है, वो देखेगा।

मुख्य मंत्री जनता दरबार में आवेदन दिया। कोई उत्तर नहीं।

गुड़गाँव से राज्य सरकार में मंत्री : देखेंगे।

केन्द्र में मंत्री जनरल : हमारा क्षेत्र नहीं है, फिर भी आप आये हो तो बात करूँगा।

भाजपा महिला प्रकोष्ठ प्रधान : अस्थाई मजदूरों की बात करते हुये फैक्ट्री में गई। बाहर निकली तो बोली कि काम की कुछ कमी है पर बात को ऊपर तक ले जाऊँगी। फिर दर्शन नहीं दिये।

विधान सभा प्रत्याशी रहे एक आये, आश्वासन दे कर चले गये।

अनशन तुड़वाने कई एच एम एस लीडर भी आये।

✶ अनशन समाप्ति के बाद भी फैक्ट्री के पास धरना जारी रखा। यह-वह करते हुये हम ने एक और गलती की।अस्थाई मजदूरों ने 23 दिसम्बर को 4-5 गाँवों के सरपंचों को मध्यस्थता के लिये बुलाया। '' हमारे क्षेत्र में कम्पनी की औकात कैसे हुई इतने वरकर निकालने की'' कहते हुये वे फैक्ट्री में गये। बाहर आ कर वो सरपंच बोले ''जब काम ही नहीं है तो कहाँ से काम दे दें।'' और हमारी कमजोरी भाँप कर धमकी दी : '' उठ जाओ नहीं तो जबरदस्ती उठायेंगे।''

तीन दिन बाद, रात को लफँगों ने टैन्ट उखाड़ दिया।

तब हम गुड़गाँव में श्रम विभाग के ए एल सी कार्यालय पर धरने पर बैठे। दिन ढलने पर पुलिस ने जबरन उठाया। दूसरे दिन मुंजाल किरियु फैक्ट्री के बाहर तीन महीने से बैठे स्थाई मजदूरों के साथ प्रदर्शन किया।रोज साँय 4½ तक धरने की अनुमति दी गई।एच एम एस लीडर ने मुंजाल किरियु वालों को कहा कि यह किसी की सुनते नहीं हैं, तुम लोग यहाँ से निकल लो।

अस्ती के अस्थाई मजदूर ही रोज धरने पर बैठने लगे। श्रम विभाग में तारीख-पर-तारीख। इस बीच कम्पनी 5-10-15 हजार होते हुये हिसाब में 25 हजार देने को तैयार हुई।आपस में चर्चायें कर हम ने निर्णय लिया। हम में से 250 ने 20.1.2015 तक हिसाब ले लिया। और 35 ने, 22 महिला तथा 13 पुरुष मजदूरों ने कोर्ट-कचहरी में तारीखों का खेल बढाया है।

कोर्ट से सम्बन्धित मामलों में ही सलाह के लिये हम ने एक

(शेष पृष्ठ चार पर)

दिल्ली सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2015 से निर्धारित न्यूनतम वेतन :

अकुशल श्रमिक	9048 रुपये मासिक (8 घण्टे के 348 रुपये)
अर्ध-कुशल श्रमिक	10,010 रुपये मासिक (8 घण्टे के 385 रुपये)
कुशल श्रमिक	10,998 रुपये मासिक (8 घण्टे के 423 रुपये)
स्नातक और अधिक	11,986 रुपये मासिक (8 घण्टे के 461 रुपये)

इस सन्दर्भ में कुछ पते :

1. मुख्य मन्त्री, ग्राउंड फ्लोर, दिल्ली सचिवालय, इन्द्र प्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली– 110002 फोन नं. 23392012, 23392201 23392020
2. श्रम मंत्री दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्र प्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली– 110002
3. श्रम आयुक्त दिल्ली सरकार, 5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली–110054 फोन नं. 23951115, 23962823 (फैक्स)

और , न्यूनतम वेतन नहीं देने, ओवर टाइम का भुगतान दुगुनी दर से नहीं करने जैसे भ्रष्टाचार के लिये दिल्ली सरकार को 1031 पर फोन करें।

हरियाणा सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 से निर्धारित न्यूनतम वेतन :

अकुशल श्रमिक	5813 रुपये मासिक (8 घण्टे के 224 रुपये)
अर्ध-कुशल ***अ***	5943 रुपये मासिक (8 घण्टे के 229 रुपये)
अर्ध-कुशल ***ब***	6073 रुपये मासिक (8 घण्टे के 234 रुपये)
कुशल श्रमिक ***अ***	6203 रुपये मासिक (8 घण्टे के 239 रुपये)
कुशल श्रमिक ***ब***	6333 रुपये मासिक (8 घण्टे के 244 रुपये)
उच्च कुशल श्रमिक	6463 रुपये मासिक (8 घण्टे के 249 रुपये)

1 नवम्बर 2014 से अकुशल श्रमिक के लिये निर्धारित 7400 रुपये न्यूनतम वेतन के बारे में हरियाणा की नई सरकार न तो हाँ कह रही है और न ही नहीं कह रही।

इस सन्दर्भ में कुछ पते :

1. मुख्य मन्त्री,चौथी मंजिल, हरियाणा सचिवालय, चण्डीगढ फोन नं. 0172-2749396 (ऑफिस), 0172-2740877 (निवास)
2. श्रम मन्त्री, पाँचवीं मंजिल, हरियाणा सचिवालय, चण्डीगढ फोन नं. 0172-2740212
3. श्रम सचिव, कमरा नं. 530, पाँचवीं मंजिल, नया हरियाणा सचिवालय, चण्डीगढ फोन नं. 0172-2713832
4. श्रम आयुक्त, 30 बेज बिल्डिंग, पहली मंजिल, सैक्टर-17, चण्डीगढ फोन नं. 0172-2701373, 2701266 (फैक्स)

✶ *अपने अनुभव व विचार मजदूर समाचार में छपवा कर चर्चाओं को और बढवाइये। नाम नहीं बताये जाते और अपनी बातें छपवाने के कोई पैसे नहीं लगते।*

✶ *बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। सड़क पर मजदूर समाचार लेते समय इच्छा हो तो बेझिझक पैसे दें ।*

✶ *महीने में एक बार छापते हैं, 13,000 प्रतियाँ निशुल्क बाँटने का प्रयास करते हैं। चर्चाओं के लिए समय निकालें।*

बहुत स्वागत योग्य

बीस मजदूरों का एक समूह ओखला, नोएडा, फरीदाबाद से सम्बन्ध रखता है। इस मजदूर समूह ने अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों से सम्बन्ध बढाने की योजना बनाई है। ओखला, नोएडा, फरीदाबाद स्थित फैक्ट्रियों के मजदूरों से नियमित चर्चायें करना और इन बातों को प्रकाशित करवा कर फैलाने का तय किया है। इसे करने के लिये बीस मजदूरों के इस समूह ने तीन-तीन, चार-चार वाली अपनी टोलियाँ बनाई हैं। मजदूरों के इस सामुहिक प्रयास की तीसरी किस्त मजदूर समाचार में प्रकाशित करते हुये हम आनन्द का अनुभव कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि कम्पनी-मैनेजमेन्ट क्या-क्या करती हैं की बजाय मजदूर क्या-क्या करते हैं वाली बातें इन साथियों से हमें मिलेंगी।

✶ दिल्ली में ओखला फेज-2 में डी एस आई डी सी स्कीम 1, शेड नं. 42 में कम्पूडाटा सर्विसेज एक प्रिन्टिंग प्रेस है। यहाँ कम्पनी द्वारा स्वयं रखे 10 मजदूरों की तनखा 7500-8000 रुपये है और पी.एफ. के कभी 650 तो कभी 750 रुपये काटते हैं। ठेकेदार के जरिये रखे 20 मजदूरों की तनखा 5000-6000 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। एक कुशल मजदूर ने दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन माँगा तो 10 मार्च को उसे नौकरी से निकाल दिया।

✶ उत्तर प्रदेश में नोएडा सेक्टर-63 में प्लॉट जे-2 स्थित ग्लोबल ट्रेडर्स में 175 वरकर काम करते हैं। ड्युटी 12 घण्टे की, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, तनखा देरी से, 20-25 तारीख को।

✶ दिल्ली में ओखला फेज-1 में प्लॉट सी-23 स्थित श्री महालक्ष्मी मैगनेट इन्डस्ट्री में फ्लोर मिल, चावल मिल, दाल मिल, गुटका फैक्ट्रियों की मशीनें बनती हैं। यहाँ हैल्पर की तनखा 6000 रुपये और कारीगर की 8000 रुपये।

✶ उत्तर प्रदेश में नोएडा सैक्टर-80 में प्लॉट ए 41 स्थित एम ए डिजाइन फैक्ट्री में भेदभाव बहुत है। एक जैसा काम कर रहे मजदूरों की तनखा में 3000 रुपये का फर्क। एडवान्स देने के मामले में भी कम्पनी बहुत दुभान्त करती है — कुछ वरकरों को देती है और कुछ को एडवान्स नहीं देती। कुछ मजदूरों से तो कम्पनी इतनी खार खाये है कि आकस्मिक छुट्टी लेने पर अनुपस्थिति लगा देती है चाहे वरकर की छुट्टियाँ बकाया हों।

✶ दिल्ली में ओखला फेज-1 में डी डी ए शेड में बी-131 स्थित द सनशाइन इन्टरप्राइजेज में किसी भी मजदूर को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं देते। यहाँ तनखायें 5700 से 8200 रुपये हैं।

कुछ अस्थाई मजदूरों......(पृष्ठ तीन का शेष)

इनकलाबी और एक क्रान्तिकारी को सलाहकार रखा है। कानून के कम जानकार लगते पर ईमानदारी से अड़ने वाले को हम ने वकील रखा है। कम्पनी और सरकार को उन्हीं के नियम-कानूनों से चुनौती देना तय किया है।

18.3.2015 को तारीख पर श्रम विभाग पहुँची कम्पनी अधिकारी बोली कि समझौता कर लो, 40 हजार दे देंगे। इनकार पर बोली की केस बहुत साल चलेगा। चलने दो....

✶ हिसाब ले चुके और कोर्ट गये अस्ती इलेक्ट्रोनिक्स के मजदूर क्षेत्र की कई फैक्ट्रियों में लग गये हैं।

अपने बीच नियमित तालमेलों के लिये हम ने एक समिति बनाई है। इनकलाबी वाले समिति में जगह चाहते थे पर हम ने मना कर दिया। हम लोगों ने तय किया है कि जहाँ भी हम काम करेंगे वहाँ बिचौलियों की दाल नहीं गलने देंगे। यूनियन की जगह हम नई चीज लायेंगे। फैक्ट्री-विशेष की बजाय औद्योगिक क्षेत्र के आधार पर संगठित होने के प्रयास हम करेंगे। ■

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए रौनिजा प्रिन्टर्स फरीदाबाद से मुद्रित किया। सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी–551 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।
RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73/15-17